माननीय न्यायमूर्ति एन. के. सोधी और एन. के. सूद, जे. जे. के समक्ष

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड व एक ओर,-अपीलार्थी

बनाम

बालबीर कौर और अन्य,-उत्तरदाता

1999 का एफ. ए. ओ. सं. 754

27 मार्च, 2000

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 149 *(2) और 170-न्यायाधिकरण दावेदारों के दावे को स्वीकार करते हुए-एक बीमाकर्ता- धारा 149 (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव कर सकता है और योग्यता के आधार पर पंचाट को चुनौती नहीं दे सकता है-बीमाकर्ता अपनी अनुमति से न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 170 के तहत योग्यता के आधार पर दावा कर सकता है-बीमाकर्ता योग्यता के आधार पर दावे को चुनौती देने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष प्रार्थना करने में विफल रहा-यह पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 170 के तहत योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती नहीं दे सकता है-अपील के साथ-साथ बीमाकर्ता द्वारा योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने के लिए दायर आवेदन-संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुरस्कार को चुनौती देने के लिए कंपनी को स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया।*

(द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रणधीर सिंह और अन्य, 1997 (1) पी. एल. आर. 532, सही कानून निर्धारित नहीं करता है)

अभिनिर्धारित किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 और धारा 170 की उप धारा (2) के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलेगा कि बीमाकर्ता से बीमित व्यक्ति के खिलाफ न्यायाधिकरण के निर्णय या निर्णय को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि वह देय लागत और ब्याज के साथ दायित्व के संबंध में निर्णय देनदार हो, बशर्ते कि बीमाकर्ता को अदालत के माध्यम से नोटिस दिया गया हो।यह भी प्रावधान किया गया है कि एक बीमाकर्ता जिसे किसी भी कार्यवाही की सूचना दी जाती है, वह उसमें पक्षकार बनने का हकदार है और अधिनियम की धारा 149 की उप धारा (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव कर सकता है और किसी अन्य आधार पर नहीं।इस उप-धारा के आधार बहुत सीमित हैं और बीमाकर्ता योग्यता के आधार पर न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने का हकदार नहीं है।हालाँकि, इस सामान्य नियम में एक अपवाद है और यह अधिनियम

की धारा 170 में निहित है। यदि न्यायाधिकरण के समक्ष जाँच के दौरान यह समाधान हो जाता है कि दावेदारों और उस व्यक्ति के बीच मिलीभगत है जिसके खिलाफ दावा किया गया है या यदि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ दावा किया गया है वह दावे का विरोध करने में विफल रहता है तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए न्यायाधिकरण बीमाकर्ता को एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अनुमति दे सकता है और उस स्थिति में इस तरह से आरोपित बीमाकर्ता को उन सभी या किसी भी आधार पर दावे का विरोध करने का अधिकार होगा जो बीमाकृत के लिए उपलब्ध हैं जिनके खिलाफ दावा किया गया था।

(पैरा 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमा कंपनी ने दावेदारों और बीमित व्यक्ति के बीच मिलीभगत का अनुरोध नहीं किया और न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को गुण-दोष के आधार पर दावे को चुनौती देने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।वास्तव में, बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण से बीमित व्यक्ति के लिए उपलब्ध सभी या किसी भी आधार पर दावे को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया।न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा नहीं करने के बाद, बीमाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष अपील में पहली बार योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अधिनियम की धारा 170 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन जिसमें गुण-दोष के आधार पर दावे को चुनौती देने की अनुमति मांगी गई है, इस प्रकार गलत धारणा है और बनाए रखने योग्य नहीं है।इसलिए, हमारा विचार है कि न केवल अधिनियम की धारा 170 के तहत आवेदन, बल्कि योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील भी विचारणीय नहीं है। कंपनी के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा।

(पैरा 5,8 और12)

एल. एम. सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, दीपक सूरी, संदीप सूरी, रोहित सूरी और सुश्री राधिका सूरी, अधिवक्ता-अपीलार्थियों *की ओर से।*

आर. एम. सिंह, प्रतिवादीगण 1 से 6 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

एन. के. सोधी, जे.

(1) यह आदेश 17 एफ. ए. ओ. संख्या 754,944,2091,2732,2733,3285,3425 से 3431,1999 के 3714,186,247 और 2000 के 460 के एक समूह का निपटारा करेगा जिसमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं।चूंकि 1999 के एफ. ए. ओ. 754 में तर्कों को संबोधित किया गया था, इसलिए इस मामले से तथ्य लिए जा रहे हैं।

(2) 14 सितंबर, 1996 को मृतक अजैब सिंह स्कूटर नं. पीबी-एलजी-6304 और मृतक दर्शन सिंह पिछली सीट पर बैठे थे।वे देवीगढ़ से गाँव बेहरू जा रहे थे।लगभग 9 बजे जब स्कूटर देवीगढ़ से लगभग एक किलोमीटर दूर पहुंचा तो ट्रक नं. एचआर-37-1340 जिसे भाग सिंह प्रतिवादी द्वारा चलाया जा रहा था।दुर्घटना के परिणामस्वरूप, अजैब सिंह और दर्शन सिंह दोनों को कई चोटें आईं।दर्शन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजैब सिंह को पटियाला के राजिंदरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।दुर्घटना के समय अजैब सिंह की आयु लगभग 42 वर्ष थी जबकि दर्शन सिंह की आयु 44 वर्ष थी।श्रीमती. दर्शन सिंह की कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते, बलबीर कौर और अन्य ने 1997 की याचिका संख्या 180 दायर की और श्रीमती. जसविंदर कौर और अजैब सिंह के अन्य उत्तराधिकारियों ने क्रमशः दर्शन सिंह और अजैब सिंह की मृत्यु के कारण मुआवजे का दावा करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अंबाला के समक्ष 1997 की याचिका संख्या 187 दायर की।इन दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया और 1997 की दावा याचिका संख्या 180 में साक्ष्य दर्ज किया गया।ट्रक का स्वामित्व भारत लाई के बेटे राम निवास के पास था और इसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास था।दावा याचिकाओं में राम निवास को प्रतिवादी संख्या 2 और बीमा कंपनी को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया था।भाग सिंह चालक को प्रतिवादी नंबर एल के रूप में शामिल किया गया था।न्यायाधिकरण राम निवास के जवाब से नोटिस मिलने पर, भाग सिंह चालक और बीमा कंपनी ने दावे का विरोध किया और दावा याचिकाओं में लगाए गए आरोपों का खंडन किया।भाग सिंह ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया जो कि प्रदर्शनी आर-2 है पक्षकारों की दलीलों से, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किएः~

(1) क्या दुर्घटना ट्रक नं. की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। एच. आर.-भाग सिंह द्वारा उत्तरदाता सं. 1 जिसके

परिणामस्वरूप दर्शन सिंह और अजैब सिंह की मौत हो गई जैसा कि आरोप लगाया गया है? ओपीपी

(2) यदि मुद्दा संख्या 1 साबित हो जाता है, तो दावेदार कितनी राशि, यदि कोई हो, के हकदार हैं और किससे? ओपीपी

(3) क्या उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तारीख को कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव।ओ. पी. आर 3

(4) राहत

(3) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायाधिकरण ने पाया कि-भाग सिंह प्रतिवादी द्वारा ट्रक को लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप अजैब सिंह और दर्शन सिंह की मृत्यु हो गई।इस प्रकार मुद्दा संख्या 1 का निर्णय दावेदारों के पक्ष में और ट्रक के मालिक, चालक और बीमाकर्ता के खिलाफ किया गया।मुआवजे की मात्रा के संबंध में, श्रीमती. बलबीर कौर और अन्य को 7,04,000 रुपये की राशि मिली, दर्शन सिंह की मृत्यु मुआवजे के रूप में और रु 5,42,000 जसविंदर कौर और अन्य मृतक अजैब सिंह के उत्तराधिकारी को। यह उल्लेख किया जा सकता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में बीमा कंपनी ने यह दलील नहीं दी कि दावेदारों और बीमित व्यक्ति के बीच मिलीभगत थी और न ही न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है जो बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति के लिए उपलब्ध सभी या किसी भी आधार पर दावे को चुनौती देने का अधिकार देता है।यह इस पुरस्कार के खिलाफ है कि बीमा कंपनी ने वर्तमान अपील दायर की है।अपील के ज्ञापन के साथ अपीलकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 170 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया है।(इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) योग्यता के आधार पर और बीमित व्यक्ति के नाम पर अपील पर मुकदमा चलाने के लिए इस अदालत की अनुमति मांग रहा है।आवेदन में की गई प्रार्थना यह है कि अपीलार्थी को योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने की अनुमति दी जाए जो याचिकाएं केवल बीमित व्यक्ति के लिए उपलब्ध थीं।अपील के आधारों को पढ़ने से पता चलता है कि बीमा कंपनी ने इस आधार पर निर्णय को चुनौती दी है कि न्यायाधिकरण ने रुपये की राशि देने में कानूनी रूप से गलती की है। दर्शन सिंह की मृत्यु के कारण मुआवजे के रूप में 7.04,000 जो राशि, अपीलार्थी के अनुसार, अत्यधिक है।इसी तरह, यह आरोप लगाया जाता है कि रु। अजैब सिंह के उत्तराधिकारियों को दिया गया 5,42,000 भी अत्यधिक है।बीमा कंपनी द्वारा की गई अपील का एक अन्य आधार यह है कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक ने दुर्घटना करने में लापरवाही नहीं की थी और इस संबंध में न्यायाधिकरण का निष्कर्ष गलत है।

(4) हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या बीमा

कंपनी को पहली बार दावेदारों के दावे को अपील में उन आधारों पर चुनौती देने की अनुमति दी जा सकती है जो बीमित व्यक्ति/उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिकों के लिए उपलब्ध हैं, उन गंडों पर दावे को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए बिना।दूसरे शब्दों में, क्या बीमा कंपनी को पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जा सकती है

क्षतिपूर्ति या इस बात पर कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक ने दुर्घटना करने में लापरवाही नहीं की थी, जब उसने उन आधारों पर न्यायाधिकरण के समक्ष दावे का विरोध नहीं किया था।इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) और धारा 170 के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैंः--

149. बीमाकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमित व्यक्तियों के खिलाफ निर्णयों और पंचाट को पूरा करें।

1 .....

2 किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी भी निर्णय या पुरस्कार के संबंध में कोई राशि तब तक बीमाकर्ता द्वारा देय नहीं होगी जब तक कि, उस कार्यवाही के प्रारंभ से पहले जिसमें निर्णय या पुरस्कार दिया जाता है, बीमाकर्ता को अदालत के माध्यम से या, जैसा भी मामला हो, कार्यवाही लाने के दावे न्यायाधिकरण को या ऐसे निर्णय या पुरस्कार के संबंध में तब तक नोटिस नहीं दिया गया था जब तक कि उस पर निष्पादन को अपील लंबित रहने तक रोक दिया जाता है और एक बीमाकर्ता जिसे ऐसी कोई कार्यवाही लाने की सूचना दी जाती है, वह इसमें पक्षकार बनने और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार होगा, अर्थात्ः–

(a) नीति, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात्ः–

(i) वाहन के उपयोग को छोड़कर एक शर्त।

(a) किराया या पुरस्कार के लिए, जहां वाहन बीमा अनुबंध की तारीख को एक वाहन है जो किराए या इनाम के लिए चलने के परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया है, या

(b) संगठित रेसिंग के लिए एक गति परीक्षण, या

(c) एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसकी अनुमति उस परमिट द्वारा नहीं दी गई है जिसके तहत वाहन का उपयोग किया जाता है, जहां वाहन एक परिवहन वाहन है; या

(d) साइड-कार को संलग्न किए बिना जहां वाहन एक मोटर साइकिल है; या

(ii) एक शर्त जिसमें किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी

ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे अयोग्यता की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है, गाड़ी चलाना शामिल नहीं है; या

(iii) एक शर्त जो परिस्थितियों या युद्ध, गृह युद्ध, दंगे या नागरिक हंगामे के कारण हुई या योगदान की गई चोट के लिए दायित्व को छोड़कर; या

(b) कि नीति इस आधार पर शून्य है कि यह किसी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या तथ्य के प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त की गई थी जो किसी विशेष रूप से किसी सामग्री में गलत थी।

(3) से (7) तक।

"170. कुछ मामलों में बीमाकर्ता को शामिल करना।–

जहाँ किसी भी जांच का पाठ्यक्रम है, दावा न्यायाधिकरण का समाधान है कि -

(a) दावा करने वाले व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच मिलीभगत है जिसके खिलाफ दावा किया गया है; या

(b) जिस व्यक्ति के खिलाफ दावा किया गया है वह दावे का विरोध करने में विफल रहा है।

यह लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता जो ऐसे दावे के संबंध में उत्तरदायी हो सकता है, उसे कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाएगा और इस तरह से शामिल बीमाकर्ता को धारा 149 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध सभी या किसी भी राशि पर दावे को चुनौती देने का अधिकार होगा जिसके खिलाफ दावा किया गया है।"

(5) ऊपर दिए गए प्रावधानों को पढ़ने के बाद, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के खिलाफ न्यायाधिकरण के निर्णय या निर्णय को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि वह देय लागत और ब्याज के साथ दायित्व के संबंध में निर्णय देनदार था, बशर्ते बीमाकर्ता को अदालत के माध्यम से नोटिस दिया गया हो।इसके अलावा यह

प्रावधान है कि एक बीमाकर्ता जिसे किसी भी कार्यवाही की सूचना दी जाती है, वह उसमें पक्षकार बनने का हकदार है और अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी भी राशि पर कार्रवाई का बचाव कर सकता है और किसी अन्य पर नहीं।इस उप-धारा के आधार बहुत सीमित हैं और बीमाकर्ता योग्यता के आधार पर न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने का हकदार नहीं है।दूसरे शब्दों में, बीमा कंपनी के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक ने दुर्घटना करने में लापरवाही नहीं की थी और न ही वह न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा के बारे में याचिका दायर कर सकती है।हालाँकि इस सामान्य नियम में एक अपवाद है और यह अधिनियम की धारा 170 में निहित है। यदि न्यायाधिकरण अपने समक्ष जांच के दौरान संतुष्ट होता है कि दावेदार और उस व्यक्ति के बीच मिलीभगत है जिसके खिलाफ दावा किया गया है या यदि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ दावा किया गया है, वह दावे का विरोध करने में विफल रहता है तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्यायाधिकरण बीमाकर्ता को एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अनुमति दे सकता है और उस स्थिति में बीमाकर्ता को इस तरह से आरोपित किया जाएगा। बीमित व्यक्ति, जिसके विरुद्ध दावा किया गया था, के लिए उपलब्ध सभी या किसी भी आधार पर दावे को चुनौती देने का अधिकार है।यदि बीमा कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष यह अनुरोध नहीं करती है कि दावेदारों और उस व्यक्ति के बीच कोई मिलीभगत थी जिसके खिलाफ दावा किया गया था और न्यायाधिकरण से अधिनियम की धारा 170 के तहत एक आदेश पारित करने के लिए नहीं कहती है जो उसे गुण-दोष के आधार पर दावे को चुनौती देने की अनुमति देता है, तो उसे अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे समक्ष मामले में, बीमा कंपनी ने दावेदारों और बीमित व्यक्ति के बीच मिलीभगत का अनुरोध नहीं किया और न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को गुण-दोष के आधार पर दावे को चुनौती देने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।वास्तव में, बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण से बीमित व्यक्ति के लिए उपलब्ध सभी या किसी भी आधार पर दावे को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया।न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा नहीं करने के बाद, हमारा विचार है कि बीमाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष अपील में पहली बार योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अधिनियम की धारा 170 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन, जिसमें गुण-दोष के आधार पर दावे को चुनौती देने की अनुमति मांगी गई है, गलत धारणा है और विचारणीय नहीं है क्योंकि ऐसी याचिका

केवल न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकती है और इस न्यायालय के समक्ष नहीं, जैसा कि धारा की सरल *भाषा से स्पष्ट है। ब्रिटिश इंडिया जनरल* इंश्योरेंस *कंपनी लिमिटेड बनाम कप्तान इतबार सिंह एण्ड अदर्स*[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह का सवाल उठा। सर्वोच्च न्यायालय के विद्वत न्यायाधीश मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 के प्रावधानों पर विचार कर रहे थे और उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न का उत्तर दियाः–

> "शुरुआत में यह याद रखना आवश्यक है कि प्रतिमा के अलावा एक बीमाकर्ता को घायल व्यक्ति द्वारा बीमित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई में पक्षकार बनाए जाने का कोई अधिकार नहीं है।हालाँकि धारा 96 की उप-धारा (2) उसे बचाव के लिए किए गए मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने का अधिकार देती है।इसलिए अधिकार क़ानून द्वारा बनाया गया है और इसकी सामग्री अनिवार्य रूप से क़ानून के प्रावधानों पर निर्भर करती है।तब वास्तव में सवाल यह है कि उप-धारा (2) बीमाकर्ता को कौन से बचाव उपलब्ध कराती है?यह स्पष्ट रूप से उप-धारा की व्याख्या का प्रश्न है।
>
> अब हमें लगता है कि उप-धारा (2) की भाषा पूरी तरह से सरल है और इसमें कोई संदेह या भ्रम नहीं है।यह है कि एक बीमाकर्ता जिसे कार्रवाई की अपेक्षित सूचना दी गई है, वह "उसमें एक पक्ष बनाने और निम्नलिखित आधारों में से किसी पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार होगा", जिसके बाद आधारों की गणना की जाती है।यह होगा कि एक बीमाकर्ता
>
> गणना किए गए किसी भी आधार पर बचाव करने का हकदार है और कोई अन्य नहीं।यदि यह पॉट था, तो निश्चित रूप से कोई आधार गिने जाने की आवश्यकता नहीं है।जब बचाव के आधार निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है।ऐसा करने के लिए क़ानून में शब्द जोड़ना होगा।

इसलिए हम सोचते हैं कि उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि एक बीमाकर्ता जिसे कार्रवाई के लिए प्रतिवादी बनाया गया है, वह कोई भी बचाव करने

[1] A.I.R. 1959 S.C. 1331

का हकदार नहीं है जो इसमें निर्दिष्ट नहीं है।"

शंकरय्या *और एक अन्य* बनाम *यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक* अन्य[2] मामले में, बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की और मुआवजे की मात्रा को कम कर दिया जब बीमित व्यक्ति ने अपील दायर नहीं की थी और बीमा कंपनी ने गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 170 के तहत न्यायाधिकरण का रुख नहीं किया था।उच्चतम न्यायालय में अपील करने पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमा कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दावे के गुण-दोष के आधार पर अपील दायर करने की हकदार नहीं है।अधिनियम की धारा 149 (2) और 170 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः–

> "यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीमा कंपनी को जब अदालत द्वारा पी आर्टी के रूप में शामिल किया जाता है तो उसे गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही का विरोध करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब धारा में उल्लिखित पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट पाई जाती हैं और उस उद्देश्य के लिए बीमा कंपनी को न्यायाधिकरण से लिखित रूप में आदेश प्राप्त करना होता है और जो न्यायाधिकरण द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए।जब तक उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक बीमा कंपनी के पास वैधानिक बचाव के माध्यम से उपलब्ध योग्यता के आधार पर व्यापक बचाव नहीं हो सकता है।"

(6) इसी तरह का दृष्टिकोण हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले द्वारा यूनाइटेड *इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम* मध्य *प्रदेश उच्च* न्यायालय के मामले में लिया गया है. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस *कंपनी लिमिटेड बनाम रामदास पाटील*[3] *मे, केरल उच्च* न्यायालय *की एक खंड पीठ द्वारा* भी, ओर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस *कंपनी लिमिटेड बनाम* के. एन. सुरेंद्रन नायर[4] और अन्य मे भी।

(7) अपीलार्थी के विद्वत वकील ने द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम *रणधीर सिंह और अन्य*[5] *में इस न्यायालय* के *एकल पीठ के फैसले पर भरोसा*

[2] 1998 A.C.J. 513
[3] A.I.R. 2000 M.P. 63
[4] A.I.R. 1990 Kerala 206
[5] 1997 (1) P.L.R. 532

किया। उनके इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि बीमा कंपनी पहली बार अपीलीय अदालत के समक्ष बीमित व्यक्ति का बचाव कर सकती है और योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती दे सकती है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निर्णय अपीलार्थी की याचिका का समर्थन करता है लेकिन हमारी राय में यह सही कानून निर्धारित नहीं करता है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 170 के तहत बीमा कंपनी के आवेदन को अनुमति देते हुए ब्रिटिश इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और *यूनिक मोटर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* बनाम करतार सिंह व एक ओर[6] मामले में इस अदालत के एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया। कर्तार सिंह। हमने इन दोनों निर्णयों को ध्यान से देखा है और पाया है कि यह कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है कि कोई बीमा कंपनी पहली बार अपील में बीमित व्यक्ति के लिए उपलब्ध बचाव को ले सकती है।

(8) इसलिए, हमारा विचार है कि न केवल अधिनियम की धारा 170 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन, बल्कि योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने वाली उसके द्वारा दायर अपील भी विचारणीय नहीं है।

(9) इस स्थिति का सामना करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि बीमित व्यक्ति के पक्ष में जारी बीमा पॉलिसी में एक खंड है जिसके तहत वह मामले के बचाव को अपने हाथ में ले सकता है और बीमित व्यक्ति के नाम पर अपने स्वयं के लाभों के लिए क्षतिपूर्ति या नुकसान या अन्यथा के लिए किसी भी दावे पर मुकदमा चला सकता है और इस अधिकार के आधार पर बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी में बीमा कंपनी द्वारा आरक्षित अधिकार के बचाव को संभालने की हकदार है, वह बचाव को अपने हाथ में ले सकती है और गुण-दोष के आधार पर विवादित पुरस्कार को चुनौती दे सकती है।विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में ब्रिटिश इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और विशेष रूप से पैरा 16 में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा कियाः–

> " हम और अधिक आश्वस्त नहीं हैं कि क़ानून
>
> किसी भी कठिनाई का कारण बनता है।सबसे पहले, बीमाकर्ता के पास अधिकार है, बशर्ते कि उसने पॉलिसी द्वारा इसे सुरक्षित रखा हो, बीमित व्यक्ति के नाम पर कार्रवाई का बचाव करने के लिए और यदि वह ऐसा करता है तो बीमित व्यक्ति के लिए खुले सभी बचाव का उसके द्वारा

[6] 1964 P.L.R. 1083

आग्रह किया जा सकता है और कोई अन्य बचाव नहीं है जिसे वह आग्रह करने का हकदार होने का दावा करता है।इस प्रकार वह बीमित व्यक्ति के नाम पर कार्रवाई का बचाव करने के अधिकार का प्रावधान करके सभी कठिनाइयों से बच सकता है और ऐसा करने की उसे पूरी स्वतंत्रता है।

(10) दावेदारों के अधिवक्ता ने दूसरी ओर कहा है की अधिनियम *की* धारा 149 की उप-धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी के पास केवल सीमित आधार उपलब्ध हैं जिन पर वह न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह कर सकती है और इस निर्णय को धारा में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।तर्क यह है कि यदि विधानमंडल चाहता था कि बीमा कंपनी द्वारा इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जाए तो इसे अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत चुनौती के लिए एक आधार बनाया गया होगा और इसमें ऐसा आधार प्रदान नहीं किया गया है कि बीमा कंपनी बचाव को अपने हाथ में नहीं ले सकती है और योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती नहीं दे सकती है।रिलायंस को के. एन. सुरेंद्रन नायर के मामले (ऊपर) में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर रखा गया है।

(11) इस प्रश्न में गए बिना कि क्या बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के खंड के आधार पर बीमित व्यक्ति के नाम पर गुण-दोष के आधार पर अधिनियम की धारा 149 (2) और 170 के प्रावधानों को अपने हाथ में ले सकती है, हमारी स्पष्ट राय है कि भले ही यह माना जाए कि इस तरह के अधिकार को अपने हाथ में लिया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग न्यायाधिकरण के समक्ष किया जाना चाहिए।न्यायाधिकरण से अनुरोध किया जाना चाहिए कि बीमा कंपनी बचाव पक्ष को अपने हाथ में ले रही है और गुण-दोष के आधार पर दावे को चुनौती दे रही है।हम श्री सूरी के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि केवल इसलिए कि बीमा कंपनी को दावे के गुण-दोष के आधार पर कुछ गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी गई थी, यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण ने उसे बीमित व्यक्ति के लिए उपलब्ध बचाव को संभालने की अनुमति दी थी।इससे पहले कि इस तरह के बचाव की अनुमति दी जा सके, न्यायाधिकरण द्वारा उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट आदेश होना चाहिए जिसमें कारण दर्ज किए जाएं।अधिनियम की धारा 170 के तहत न्यायाधिकरण से कोई आदेश प्राप्त नहीं करने के बाद, बीमा

कंपनी को उपलब्ध बचाव कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस न्यायालय के समक्ष अपील में पहली बार बीमाकृत।

(12) अंत में यह तर्क दिया गया कि ऐसा हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में एक बीमा कंपनी को यदि योग्यता के आधार पर या मुआवजे की मात्रा के संबंध में पुरस्कार को चुनौती देने का अधिकार नहीं दिया जाता है जो अत्यधिक और अनुचित हो सकता है, तो एक गंभीर अन्याय किया जा सकता है और कंपनी के पास कोई उपाय नहीं होगा।हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं।एक उपयुक्त मामले में कंपनी के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस अदालत से संपर्क करने का अधिकार होगा।

(13) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा